RAJYA SABHA

Tuesday, the 7th August, 2001 / 16 Sravana, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Waiting List for telephone connections in Mandvi, Gujarat

*221. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is a long waiting list for telephone connections in Mandvi in Kutch region of Gujarat;

(b) if so, the details thereof, exchange-wise; and

(c) the steps being taken to clear the waiting list?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The waiting list in Mandvi exchange is 750 and the total waiting list in Mandvi SDCA (Short Distance Charging Area) is 2143.

(b) The exchanges-wise details of waiting list in Mandvi SDCA are given in Statement-I (*See* below).

(c) (i) Underground cable laying works are in progress to make the technically non-feasible (TNF) areas of Mandvi SDCA feasible.

(ii) 1000 lines exchanges using Wireless in Local Loop (WLL) technology has been planned for the year 2001-2002 for Mandvi town to clear TNF cases, which are not being covered by laying underground cable as per norms.

(iii) The waiting list is likely to be cleared by March, 2002.

Statement-I

Exchange-wise details of waiting list including pending OBs (work orders) of Mandvi SDCA in Kutch District

Sl. No.	Name of Exchange	Waiting List including Pending OBs
1.	Bada	27
2.	Bidada	258
3.	Darsadi	98
4.	Gadhsisa	298
5.	Gangapar	41
6.	Godhra	32
7.	Koday	138
8.	Laiza Mota	50
9.	Mota Asambia	31
10.	Mandvi	750
11.	Nana Bhadia	49
12.	Padampur	07
13.	Rampar	99
14.	Subhrai	37
15.	Sirva	110
16.	Wada	118
	TOTAL:	2143

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति जी, मैंने जो सवाल किया था, उसका जवाब एन.डी.ए. की सरकार और मंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से दिया है। वैसे भी मैं इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके डिपार्टमेंट ने कच्छ में आए भूकम्प के समय बड़ी अच्छी कार्रवाई की और पर्टिकुलरली मांडवी टाउन में भी बहुत बड़ा काम किया। मैंने जो भी सवाल किया था, उसका सही तौर पर मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला है, इससे मुझे बहुत संतोष है। मैं केवल एक ही प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डब्ल्यू॰एल॰एल॰ लाइन आपने 1000 दी हैं, इन लाइनों की जहां कमी हैं, वेटिंग लिस्ट चल रही है और पार्टिकुलरली देहात व गांव में, जहां छोटे-छोटे किसान और गरीब लोग रहते हैं, वहां टेलिफोन की जरूरत है, वहां आप जल्दी से जल्दी टेलीफोन दें, ऐसी मेरी आपसे और आपके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है और चूंकि आपने बहुत संतोषकारक जवाब दिया है, इसलिए मैं दूसरी सप्लीमेंटरी नहीं पूछना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, कच्छ या भुज में नेचुरल केलामिटी कहिए या जो आपदा आई, वह पूरे देश के लिए एक बहुत चिंता का विषय था और उस दृष्टिकोण से टेलिकॉम डिपार्टमेंट से जो भी बन पाया, उस पर जल्दी से जल्दी हमने कार्रवाई करने का कार्य किया। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस समय मेरे पास 147 एक्सचेंज थे, जिन्हें अभी हमने बढ़ाकर 205 कर दिया है और मैंने स्वयं उसका मॉनिटरिंग किया है और जितनी भी वेटिंग लिस्ट हैं, उसमें पहले 2500 का काम किया गया था, मैंने कल ही उसकी क्षमता बढ़ाकर के करीब-करीब 3,500 करने का काम उस जिले में किया है। माननीय सदस्य ने जो डब्ल्यूएलएल के बारे में कहा है, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसके माध्यम से कनेक्शन देने का काम करेंगे।

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने प्रतीक्षा सूची 2143 की बताई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ये जो 16 एक्सचेंज हैं, इनमें कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं और क्या यह सच है कि जहां भी कनेक्शन दिए गए हैं वहां के कई गांवों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहां पर कनेक्शन तो हैं लेकिन फाल्ट होने के कारण वे चलते नहीं हैं, फोन चलते नहीं हैं और बहुत समय बीत जाने के बाद भी वे फाल्ट रिपेयर नहीं किए जाते हैं और उसके कारण लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है? अगर मंत्री जी यह भी बताएं कि गुजरात में गांवों में प्रतीक्षा सूची कितनी है तो बड़ी कृपा होगी।

श्री राम विलास पासवान: सर, 16 एक्सचेंज हैं और 16 एक्सचेंज में बाडा में कैपिसिटी 304 है, वर्किंग कनेक्शन 198 हैं , वेटिंग लिस्ट केवल 27 की है। बिडाडा में 1000 का है, वर्किंग कनेक्शन 730 हैं, 228 पेंडिंग हैं, लेकिन 500 की कैपिसिटी हम बढ़ाने जा रहे हैं। डारसाडी में 336 का है, 260 अभी वहां कनेक्शन हैं, 98 पेंडिंग हैं और 256 लाइन हम और देने जा रहे हैं। गढ़सिसा में 1400 की कैपिसिटी है, 934 वर्किंग कनेक्शन हैं, 298 वेटिंग लिस्ट हैं, 500 लाइन हम बढ़ाने जा रहे हैं। इसी तरीके से गंगापार है, यहां 272 की कैपिसिटी है, 168 कनेक्शन हैं, 32 वेटिंग लिस्ट है, इसलिए वहां कैपेसिटी बढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है। कोडाय में 304 की कैपिसिटी है, 243 वर्किंग कनेक्शन हैं और 138 वेटिंग लिस्ट है वहां 500 लाइन हम बढ़ा रहे हैं। लेयजामोता में 336 की कैपिसिटी है, 185 वर्किंग कनेक्शन हैं, 50 वेटिंग लिस्ट है, इसलिए वहां बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोता असम्बिया में 152 की कैपेसिटी है, 146 वर्किंग है, 31 वेटिंग लिस्ट में हैं और 256 हम वहां पर बढ़ा रहे हैं। मांडवी में 4,000 की कैपेसिटी है, वहां अभी 3,804 कनेक्शंस हैं, 750 वेटिंग लिस्ट में है और 1,000 की लाइन हम बढ़ा रहे हैं। नाना भडिया में 184 की कैपेसिटी है, 108 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 49 वेटिंग लिस्ट में हैं, इसलिए वहां बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पदमपुर में 152 की कैपेसिटी है, 147 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 7 वेटिंग लिस्ट में हैं और 256 हम बढ़ा रहे हैं। रामपार में 184 की कैपेसिटी है, 62 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 99 वेटिंग लिस्ट में है और 256 हम बढ़ा रहे हैं। सुभराय में 304 की

कैपेसिटी है, 180 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 37 वेटिंग लिस्ट में हैं, वहां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिरवा में 304 की कैपेसिटी है, 263 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 110 वेटिंग लिस्ट में हैं और 256 हम बढ़ा रहे हैं। वाडा में 1,000 की कैपेसिटी है, 521 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 118 वेटिंग लिस्ट में है, इसलिए वहां बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह कुल मिलाकर 10,536 की कैपेसिटी है, 8,200 वर्किंग कनेक्शंस हैं, 2,143 वेटिंग लिस्ट में हैं और 3,780 हम बढ़ा रहे हैं।

जहां तक आपने गुजरात की बात कही है, गुजरात में कुल कैपेसिटी 30,09,340 है, 24,51,804 वर्किंग कनेक्शंस हैं, इस तरीके से कुल मिलाकर वेटिंग लिस्ट 2,38,974 की है लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हमारा ऐक्शन प्लान है, उस प्लान के अंतर्गत इस वेटिंग लिस्ट को जल्दी से कैसे खत्म किया जाए, इस बारे में हमने अपना कार्यक्रम बना लिया है।

श्री ललितभाई मेहता: उसमें बंद कितने हैं?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, हम फॉल्ट रेट दे सकते हैं कि गुजरात का फाल्ट रेट क्या है लेकिन इंडिविजुअल टेलीफोन कहां-कहां बंद हैं, यह बताना संभव नहीं है।

श्री ललितभाई मेहता: केवल यह बता दीजिए कि उसे रिपेयर करने में कितना समय लगता है?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, फाल्ट रेट 20.99 है और फाल्ट रिपेयर का ऐवरेज 23 घंटे है।

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Sir, I would request the hon. Minister to state the position of telephone-density in India, as of today, and also state our position in comparison with China and Pakistan; and if there is a leeway, I want to know how the Government proposes to undo it.

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, अभी पूरे देश में 3 करोड़ 29 लाख टेलीफोन की लाइनें हैं और 45 लाख सेलुलर फोन हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो टेली-डेंसिटी बढ़कर 3.6 हो जाती है। यह बात सही है कि वर्ल्ड की टेली-डेंसिटी प्रत्येक 100 पर 15 है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी बहुत ज्यादा है लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने टेली-डेंसिटी को डबल किया है। जब हम आए थे तो उस समय 2 करोड़ लाइनें थीं और आज इन लाइनों की संख्या बढ़कर साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा हो गई है। हमारा टारगेट है कि 2005 तक हम टेली-डेंसिटी को बढ़ाकर प्रत्येक 100 पर 7 करें और उसके लिए हम 7 करोड़, 50 लाख लाइनें लगाएंगे। पिछले साल हमारा टारगेट था 45 लाख लाइनें लगाने का, जब कि हमने 50 लाख लाइनें लगाईं। इस बार भी हमारा जो टारगेट है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 2010 तक हमारा टारगेट टेली-डेंसिटी को बढ़ाकर प्रत्येक 100 पर 15 तक करने का है। उसके लिए साढ़े सात करोड़ लाइनें लगाने

की योजना है लेकिन इसके लिए काफी पैसे की आवश्यकता है। इसके लिए 2005 तक 38 बिलियन अमेरिकन डालर्स चाहिए और 2010 तक 78 बिलियन अमेरिकन डालर्स चाहिए। इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। इसलिए जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं, उनके लिए हमने लिब्रलाइज़ कर दिया है।

सभापति महोदय, जहां तक चीन का सवाल है, चीन से हम तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे अपने बजट का कुल एक-तिहाई हिस्सा टेलीकाम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जब कि हमारे पास जो पैसा आता है, हम उसी में से अरेंज करते हैं।

प्रो. रामदेव भंडारी: माननीय सभापति जी, सांसदों की अनुशंसा पर प्रायोरिटी बेसिस पर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है और वह टेलीफोन कनेक्शन एक महीने में उपलब्ध करा देना होता है। मगर कभी-कभी तीन महीने, छः महीने, 9 महीने तथा साल भर भी लग जाता है, कभी-कभी सांसदों की अनुशंसा पर जो टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। कभी कहते हैं कि फिजिबल नहीं है और कई तरह के कारण बतलाए जाते हैं तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह फिजिबल नहीं है तो उसको फिजिबल बनाया जाए, अगर पोल नहीं है, खम्भा नहीं है, तार नहीं है तो उसको उपलब्ध कराया जाए। कितना समय लेंगे वह सांसदों की अनुशंसा पर टेलीफोन कनेक्शन देने में यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री राम विलास पासवान: सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी हैं, कहीं रेगिस्तान है और माननीय सदस्यों को पूरी आजादी है कि वह देश के प्रत्येक कोने में से किसी कोने के लिए वह एप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमारे पास में कोई ऐसा साधन होना चाहिए कि उस गांव तक पहुंच जाएं। जहां तक शहर का मामला है, जहां टेलीफोन की लाईन उपलब्ध है वहां तो सांसदों की अनुशंसा पर तुरन्त टेलीफोन लगा देते हैं। जहां तक दूरदराज का इलाका है वहां दिक्कत होती है और उस व्यवधान को खत्म करने के लिए हमने डब्लयू.एल.एल. सिस्टम-वायरलैस इन लोकल लूप की शुरुआत की है। वह वायरलैस इन लोकल लूप ऐसा है कि जहां 24 किलोमीटर की दूरी तक उसमें न तार की जरूरत है और न किसी चीज की जरूरत है। जो मार टेक्नोलोजी है उससे भी यह अलग है। चूंकि मार टेक्नोलोजी दो लाख ग्यारह हजार गांवों में काम कर रही है लेकिन उसमें से करीब-करीब 60-70 परसेंट खराब है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि उसको भी हम चेंज करेंगे ऐसे छः लाख सात हजार गांव हैं तो इस परिस्थिति में हम डब्लयू.एल.एल. टेक्नोलोजी लाए हैं हालांकि उस पर बहुत विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में भी है। लेकिन डब्लयू.एल.एल. टेक्नालजी के माध्यम से एक जगह भी अगर हम बेस स्टेशन बनाते है तो 25 किलोमीटर की दूरी तक किसी लाईन की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है और उसके माध्यम से हमने 6 लाख लाईन लगाने का निर्णय लिया है। इसके टेंडर वगैरह फाइनलाइज हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि हर स्टेट को डिस्ट्रिब्यूट किया जा चुका है और जल्द से जल्द डब्लयू.एल.एल. के माध्यम

से जो दूरस्थ इलाका है वहां टेलीफोन की सुविधा दी जाएगी और उसमें प्राथमिकता माननीय संसद सदस्यों का जो आग्रह है या जो आपका कोटा है उसको देंगे।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति जी, धन्यवाद! वैसे मेरा यह प्रश्न अनायास ही मंत्री जी के उत्तर से उत्पन्न हो गया है। आपने जैसा कहा कि इस देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं नदी हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं घाटी है, कहीं कुछ है। तो इसमें इस सब के बावजूद एक रामविलास पासवान भी इस देश के पास हैं इतना और जोड़ लें। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश में मार पद्धति नष्ट ही नहीं मृत प्राय: हो गई है और उसको सरकार कब डैड घोषित कर देगी इसकी कोई गारंटी अभी तक देने के लिए आप तैयार नहीं है और इसके बहाने इस देश में बड़ी अराजकता आपके विभाग में हो रही है। क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात को वह सारी पद्धति नष्ट हो गई है और सारा का सारा देश अब प्रतीक्षा कर रहा है आपके डब्लयू.एल.एल. सिस्टम की ओर उस दिशा में मार के मोह से कब हमें छुट्टी दे करके नई टेक्नोलोजी के आधार पर इस देश को खड़ा कर देंगे? एक तो मेरा आपसे यह आग्रह है। दूसरे मैं खुद हिमाचल में घूम करके आया हूं। वहां छ:-छ: साल से सांसदों की अनुशंसा किए हुए बिना बारी वाले टेलीफोन के प्रकरण अभी तक लम्बित पड़े हुए हैं। उन सब का फैसला कब तक हो जाएगा? अगर इन दो बातों पर आप प्रकाश डाल सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री राम विलास पासवान: जहां तक मार का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि दो लाख ग्यारह हजार गांवों में मार टेक्नोलोजी लगाई गई थी। हो सकता है कि जिस समय मार टेक्नोलोजी लाई गई थी वह बढ़िया टेक्नोलोजी हो लेकिन आज के समय में हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि इसमें 30 परसेंट लाइन खराब हैं लेकिन मैं जानता हूं कि 80 परसेंट खराब हैं।

श्री बालकवि बैरागी: सर, अगर आप सेंट-परसेंट मान लेंगे तो इस देश पर बहुत कृपा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: थोड़ा बहुत श्याम टेलीकॉम वगैरह का है। उनसे जब एग्रीमेंट वगैरह किया गया था उस एग्रीमेंट में मेंटीनेंस का जो होना चाहिए था वह एग्रीमेंट में नहीं था। नतीजा यह है कि जो टेक्नोलोजी लगा कर चले गए उस टेक्नोलोजी के बारे में अभी किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यह ऐसा कारण है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि फेज-वाइज अगले दो साल के अंदर जितनी भी मार टेक्नोलोजी है उसको चेंज करके हम उसकी जगह पर डब्लयू.एल.एल.टेक्नोलोजी लगाएंगे। जहां-जहां हमारी लाइनें जा रही हैं वहां-वहां हम तो वैसे ही रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो बच जायेगा वहां पर हम डब्लयू.एल.एल. टेक्नालॉजी लेकर उसको रिप्लेस करेंगे। माननीय संसद सदस्यों का जहां तक सवाल है, मैंने कहा कि डब्लयू.एल.एल. टेक्नालॉजी आ गई है और उसके कारण से अगले छह महीने के अंदर सुदूर से सुदूर तक किसी भी इलाके में यदि आपने अनुशंसा

की है उसको भी टेलीफोन मिल जायेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम छह महीने तक वेट करेंगे। जहां तक संभव होगा हम हर डिस्ट्रिक्ट में बेस स्टेशन लगवा रहे हैं और बहुत जगहों पर डब्ल्यू.एल.एल. टेक्नालॉजी के बेस स्टेशन लगवा भी दिए गए हैं। जहां-जहां ये शुरू होते जायेंगे, वहां-वहां हम करते जायेंगे। आपने जो मैक्सिमम टाइम मांगा है उसके संबंध में मैं कहता हूं कि नेक्स्ट छह महीने के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं रहेगा। जहां आपने टेलीफोन के लिए अनुशंसा की हो और हम उसको टेलीफोन न दे सकें।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, for the last few days, we were hearing about the Government's defence on other issues and finding fault with a particular business house based in Mumbai. But the Minister has referred to the tender finalisation about the WLL technology. Now, we are given to understand that very particular company has been given licence for operating telecom services in 16 circles, without a bid. Will the Minister be kind enough to give us the details about this matter?

MR. CHAIRMAN: As a matter of fact, this question is confined to Gujarat. Since the hon. Members wanted to know about the MPs' quota, I just allowed it.

SHRI NILOTPAL BASU: Since he referred to it.....(*interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. We go to the next question. I cannot refuse others. ...(*interruptions*)... This is opening the Pandora's box.

SHRI NILOTPAL BASU: That is a problem, Sir. We understand it.

MR. CHAIRMAN: Question No. 222, Shri K.C. Kondaiah.

Air services from Hubli and Belgaum airports

*222. SHRI K.C. KONDAIAH: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hubli and Belgaum airports are not being made functional;

(b) if so, whether there is any proposal to invite private air operators to introduce their services on Belgaum-Hubli-Bangalore-Chennai and Mumbai-Hubli-Bangalore-Chennai routes twice a week; and

(c) whether Indian Airlines is also considering to operate its services on these routes?